RAJYA SABHA

Tuesday, the 11*th March*, 2003/20 *Phalguna*, 1924 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Subsidy on LPG Cylinder

*281. DR. ABRAR AHMED:††
SHRI RAJEEV SHUKLA:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the average subsidy per cylinder (LPG) during the last two years, year-wise, against its total price;

(b) whether there is any proposal to inrease the LPG prices; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Average subsidy per cylinder on domestic LPG during 2000-01 and 2001-02 was Rs. 150.55/cylinder and Rs. 115.63/cylinder respectively. The retail selling prices of this product in Delhi during these years were as follows:

On	Rs./Cylinder
01.04.2000	196.55
30.09.2000	232.25
22.11.2000	222.25
01.03.2002	259.95
17.03.2002	240.45

††The Question was actually asked on the floor of the House by Dr. Abrar Ahmed.

(b) and (c) From 1st April 2002, subsidy on domestic LPG is being provided at the flat rate of Rs. 67.75 per cylinder. The changes in the consumer price of domestic LPG after providing for the flat rate of subsidy are to be made by the oil marketing companies. The issue of price revision of domestic LPG is under consideration of the oil marketing companies.

डा॰ अबरार अहमद: माननीय सभापति महोदय, अभी जनरल बजट की स्याही सूखी भी नहीं थी और उसमें जो लोक लुभावने नारे थे, ''गरीब के पेट में दाना, महिलाओं की रसोई में आना'' वे आम लोगों तक पहुंचे भी नहीं थे कि अखबारों में यह पढ़ने को मिला और माननीय मंत्री जी कोलकाता गये तो वहां से एक संकेत इन्होंने दिया की एल॰पी॰जी॰ गैस की कीमत में वृद्धि हो सकती है। कुछ अखबारों ने निश्चित रूप से.....

श्री सभापति: आप सीधा पूछ लीजिए कि वृद्धि करने का आपने स्टेटमेंट दिया है?

डा॰ अबरार अहमद: मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां बदली कि बजट के अंदर मूल्य वृद्धि नहीं हुई और उसके बाद उन्हें तीन दिन के बाद यह बात कहनी पड़ी।

श्री सभापति: अबरार साहब, आप सीधा प्रश्न कर लीजिए कि आपने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है या नहीं दिया है?

डा॰ अबरार अहमद: सर, मैं अपना पूरा सप्लीमेंटरी कह दूं वरना मेरी अपार्चुनिटी...

श्री सभापति: सप्लीमेंटरी में डिबेट नहीं होने देंगे। भूमिका मत बांधिए।

डा॰ अबरार अहमद: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी परिस्थिति बदली थी जिससे यह बात बजट के चार दिन बाद ही सामने आयी? दूसरा जो एल॰पी॰जी॰ गैस की मुल्य प्रणाली है, उसके अंदर सब्सिडी के बारे में आपने उत्तर में बताया है कि ''स्थायी दर पर राजसहायता 67.75 रुपए प्रति सिलेंडर की समान दर पर उपलब्ध कराई जा रही है''। उसके बाद भी 60 से 70 रुपए जैसा अखबारों में आया है कि उसकी कीमत कम रह जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो सब्सिडी है, आज देश का अमीर से अमीर आदमी भी उस सब्सिडी का लाभ ले रहा है। मैं मूल बात यह पूछना चाहता

श्री सभापति: मूल बात अभी तक नहीं आयी है क्या? पांच मिनट हो गये हैं।

डा॰ अबरार अहमद: इस सब्सिडी का लाभ आज आप, मैं, टाटा, बिरला, प्रेमजी, हर आदमी ले रहा है। उसके घर में गैस सिलेंडर जलता है। राजसहायता के 67.75 पैसे का वह भी लाभ उठा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी इस सब्सिडी का लाभ उस गरीब आदमी को देंगे जो वास्तव में इसका हकदार है? मौलिक प्रश्न यह है।

श्री सभापति: देखिए, मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री राम नाईक: महोदय, यह बात सही है कि सब्सिडी के बारे में पहले की जो प्रणाली थी, उसमें परिवर्तन कराकर अब फ्लैट रेट ऑफ सब्सिडी दी जाती है जो 97 में उस समय की सरकार ने एक नीतिगत तौर पर तय की थी। अप्रैल 2002 में एल॰पी॰जी॰ की कीमत प्रति मीट्रिक टन 197 थी वह अब 370 डॉलर्स हो गयी हैं इस प्रकार इसमें 80 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोत्तरी हो गयी है। इसलिए जब हमको विदेश से लाना पड़ता है तो कीमत ज्यादा देनी पड़ती है। इसलिए फिक्स्ड सब्सिडी छोड़कर, बाकी का ऑयल कम्पनियां तय करती है कि कितना बढ़ाना है, कितना अपने पास रखना है या कम करना है। यह ऑयल कम्पनियों के दायरे में आता है इसलिये इस पर वे विचार करेंगी। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि गरीब की बात हुई है, हमारे आस-पास के जो देश हैं, जैसे नेपाल है, नेपाल में इस समय एक सिलेंडर की कीमत...

श्री सभापति: अब आप नेपाल को छोड़िए।

श्री राम नाईक: हमारे यहां एक सिलेंडर की कीमत 241 है तो नेपाल में 408 रुपए है, 167 रुपए ज्यादा है। इसी प्रकार श्रीलंका में 311 है जो कि 70 रुपए ज्यादा है। सभी आस-पास के देशों में यह स्थिति है। बड़ी मुश्किल से हम इसे चला रहे हैं हमें भी कष्ट होता है जब कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हैं।

डा॰ अबरार अहमद: महोदय मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोलकाता में जो संकेत दिया, जो अखबार में छपा, जिसके संबंध में माननीय सभापति महोदय ने भी आपको कहा, वह सही है या नहीं कि एल॰पी॰जी॰ सिलेंडर की कीमत बढ़ सकती है? आपने ऐसा कहा था या नहीं?

श्री राम नाईक: मैंने उत्तर में भी कहा था कि ऑयल कम्पनीज़ The issue of price revision of domestic LPG is under consideration of the Indian marketing companies. इस प्रकार कम्पनियां तय करेंगी और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ेंगे तो उसके अनुसार वे कुछ न कुछ निर्णय करेंगे।

श्री सभापति: श्री राजीव शुक्ल।

डा॰ अबरार अहमद: सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है।

श्री सभापति: आपके दोनों सप्लीमेंटरी हो गये हैं। आपके चार प्रश्न हो गये हैं। मैं अब और अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री राजीव शुक्ल: महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि खबर आयी थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 71 रुपए की सब्सिडी दी है जबकि उनके जवाब में 67.75 रुपए की सब्सिडी बतायी गयी है? दूसरा पैट्रोलियम मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिक्वैस्ट की थी कि 16 परसेंट ऐक्साइज ड्यूटी को ऐक्ज़म्प्ट के लिए रिक्वैस्ट की थी, उस बारे में क्या प्रगति हुई है?

श्री राम नाईक: सभापति महोदय, वित्त मंत्री हर मंत्रालय के साथ चर्चा करते हैं। हमने भी अपने सुझाव दिए थे, उन सब पर विचार करके ही वे निर्णय करते हैं। और अभी जो निर्णय है, वह 16 परसेंट एक्साईज़ ड्यूटी एल.पी.जी. पर है। बाकी पहले प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, from 1st April, 2002 the Government have dismantled the administered pricing system with regard to petroleum products. We have been told that we have moved on to a new system of market determined prices. But newspapers have been persistently reporting that we have replaced the administered pricing system by the Naik determined pricing system in which the Minister of Petroleum is fixing the prices. I would like the hon. Minister to tell us, what is the system that is being followed now for fixing petroleum prices after the dismantling of the administered pricing system.

SHRI RAM NAIK: The oil companies look into the international prices and take their decisions, but when the prices become very volatile, we also try to see if we can help the consumers so that they are insulated from very high price-increase.

In that context, excise duty adjustments can be done. Accordingly, last June, we reduced the excise duty thereby reducing the burden. So far as taxation is concerned; excise duty, customs duty, we do look into it so that consumers are a little insulated from the heavy prices in international market.

DR. MANMOHAN SINGH: That was not my question. It has been reported that the oil companies want to raise prices and the Minister had prevented them from raising these prices. I would like to know whether that is a fact or not.

SHRI RAM NAIK: It is not at all a fact.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, supply of LPG through pipeline to all the consumers is long overdue. At least, the Ministry should finalise a deadline to complete this project for major cities. Let the Minister spell out the date for completion of such project.

SHRI RAM NAIK: Sir, nowhere there is a proposal for supplying LPG through pipeline within a particular city, but we are bringing LPG gas through the longest pipeline in the world, covering 1400 KMs, from Gujarat to Delhi. So, LPG is brought....*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: *Via* Rajasthan.

SHRI RAM NAIK: Yes, Sir, *via* Rajasthan, *via* Madhya Pradesh, *via* Haryana to Delhi. But the point is that we are trying to see if we can devolve a system like that. But at present only some cities in a particular housing complex, if they take on wholesale basis, then, they supply through their retail price. That type of experiment is going on, but no decision has been taken so far.

नेपाल से बहने वाली नदियों पर बांध

*282. **प्रो॰ राम देव भंडारी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेपाल से उद्भूत और बिहार से होकर बहने वाली नदियों पर बांध बनाने के लिए भारत और नेपाल के बीच चल रही वार्ता में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस वार्ता में बिहार सरकार के प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है; और

(ग) बिहार में इन नदियों से होने वाली बाढ़ की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत और नेपाल के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जुलाई-अगस्त, 2000 के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसरण में नेपाल से निकलने वाली नदियों में बाढ़ नियन्त्रण के लिए भंडारण स्कीमों अर्थात कोसी नदी पर सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना और सनकोसी भंडारण व व्यपवर्तन स्कीम, कमला नदी पर कमला बहुउद्देश्यीय परियोजना और बागमती नदी पर बागमती बहुउद्देश्यीय परियोजना सहित भारत और नेपाल के बीच जल संसाधनों सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए जल संसाधनों संबंधी भारत-नेपाल संयुक्त समिति का गठन किया गया था।